<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

06 अप्रैल, 2018

<u>श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान:-</u>

‘‘51 वर्षों के सबसे बड़े भर्ती घोटाले ने सीएम, श्री खट्टर के झूठे दावों का किया पर्दाफाश’’
‘‘हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बोली लगाकर बेच रही खट्टर सरकार’’
‘‘नौकरियां बिकतीं बीच बाजार, मेरिट से नहीं सरोकार,
ऐसी रही खट्टर सरकार!’’

मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर के मनोनीत चहेतों द्वारा संचालित **‘कर्मचारी चयन आयोग’ अब भ्रष्टाचार व नौकरियां बेचने वाले माफिया का अड्डा बन गया है। 51 वर्षों में हरियाणा के सबसे बड़े ‘रोजगार दलाली घोटाले’ ने श्री खट्टर के पारदर्शिता के आधार पर ईमानदारी से नौकरी देने के खोखले दावों की पोल खोल दी है।**

भाजपा सरकार में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, छल और कपट की परतें अब हरियाणा की जनता के सामने उजागर हैं। ‘एक परिवार, एक रोज़गार’ व नौजवानों को 9000-12000 रु. मासिक बेरोजगारी भत्ता का वायदा कर सत्ता में आई खट्टर सरकार में बोली लगाकर सरकारी नौकरियां खुलेआम बेची जा रही हैं।

नौकरियां बेचने के खुले खेल को खट्टर सरकार का सीधा संरक्षण प्राप्त है। पर अब खट्टर सरकार चंद छोटे दलालों को गिरफ्तार कर नौकरियों की दलाली करने वाले गिरोह के सरगनाओं को बचाने में लगी है। इस नौकरी दलाली घोटाले के लिए अगर जवाबदेही और जिम्मेवारी किसी की है, तो वह सीधे सीधे श्री मनोहर लाल खट्टर तथा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की।

<u>प्रश्न</u>

1. अब यह साफ है कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी एक वर्ष से है तथा पिछले 8 महीने से आरोपियों की टेलीफोन टैपिंग इत्यादि चल रही थी। **क्या मुख्यमंत्री, श्री खट्टर बताएंगे कि फिर उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन, श्री भारत भूषण भारती को तीन साल की एक्सटेंशन व सभी सदस्यों को एक-एक साल की एक्सटेंशन क्यों दी?**

2. **क्या यह सही नहीं कि हाल में ही एक ऑडियो टेप जारी हुआ, जिसमें कथित तौर से कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की बातचीत में पेहवा नगरपालिका के अध्यक्ष हेतु 80 लाख रु. की मांग की जा रही है? क्या कारण है कि इसकी सच्चाई की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाए बगैर ही श्री खट्टर ने चेयरमैन को क्लीनचिट दे दी तथा साथ साथ ही तीन साल की एक्सटेंशन भी?**

3. जब पुलिस लगभग एक साल से नौकरी भर्ती घोटाले की जांच कर रही थी, तो फिर हेराफेरी की जानकारी होते हुए भी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नौकरी, भर्ती और बिक्री खट्टर सरकार की नाक के नीचे कैसे चल पाई? **मुख्यमंत्री व सरकार ने इस नौकरी दलाली घोटाले को एक साल तक रोका और पकड़ा क्यों नहीं?**

4. **क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए भर्ती घोटाले के तथाकथित किंगपिन, श्री पुनीत सैनी की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन, श्री भारती द्वारा नहीं की गई?** क्या यह सब 25 अगस्त, 2017 को पंचकुला हिंसा और कर्फ्यू के दौरान कर्मचारी चयन आयोग की बिल्डिंग में नहीं मौजूद थे? क्या इस बात की जानकारी 25 अगस्त, 2017 को पुलिस को नहीं चल गई थी, जब बाहर खड़े इनके मोटरसायकल इत्यादि उग्र भीड़ द्वारा जला दिए गए? **तो फिर 25 अगस्त, 2017 से 5 अप्रैल, 2018**

तक खट्टर सरकार क्यों सोई रही?

5. **क्या यह सही नहीं कि खट्टर सरकार में 19 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें जजों की नियुक्ति से लेकर और कल ही यमुनानगर में लीक हुए टैक्सेशन इंस्पेक्टर का शामिल है? क्या मुख्यमंत्री, श्री खट्टर 19 लीक पेपर की संलग्न सूची के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे?**

कुछ छोटे कर्मचारियों व नौकरी बेचने वाले छोटे दलालों पर मुकदमा दर्ज कर मुख्यमंत्री, श्री खट्टर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब भाजपा सरकार की जवाबदेही और नौकरी दलाली घोटाले के सरगनाओं की कलई खोलने का समय आ गया है। **हरियाणा के युवाओं की ओर से हमारी मांग है कि:-**

I. नौकरी भर्ती घोटाले की जांच पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत दो पदासीन न्यायाधीशों के कमीशन से तीन महीने के अंदर करवाई जाए।
II. कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को फौरन बर्खास्त किया जाए।
III. कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को एफआईआर में आरोपी के तौर पर नामज़द किया जाए?
IV. मुख्यमंत्री कार्यालय, कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों के ऑफिस तथा निवास के सभी कंप्यूटर्स को जब्त कर उनकी फोरेंसिक जांच करवाई जाए व न्यायिक आयोग के समक्ष पेश की जाए?
V. करोड़ों रुपये की राशि, जो हरियाणा के नौजवानों से रोजगार के नाम पर लूटी गई है, उसे वापस करवाया जाए तथा इस बारे सभी युवाओं से, जो रिश्वत देने के शिकार बने हैं, उनसे जानकारी एकत्रित कर उनके पैसे लौटाए जाएं व पैसे लेने वाले सब दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाए?